



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 3
PART III—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]
No. 5]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 1984/चैत्र 14, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3 1984/CHAITRA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सद्य शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन

मपौदा नियम

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

मिलवासा, 3 अप्रैल, 1984

सं० प्रशा०/रा० वि०/924/1984 —प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली, भिन्न मपौदे नियत नियम के बारे में धारा-37 के अधीन प्रवर्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित कार्यावाई के लिये यह बम्बई निवारण एवं दुर्घीकरण चकबन्दी अधिनियम, 1947 (1947 का बम्बई अधिनियम सं०-62) को सुजराण राज्य में विस्तारित किया गया था। इसे अभी सद्य शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली पर भारत सरकार गृह मन्त्रालय की अधिसूचना सं० ओ एम आर/869 (ई०), दिनांक 30-11-1983 से यथाविस्तारित किया गया है अतः इस विषय में निम्न की धारा-37 की उप-धारा-(3), के तहत प्रकाशित किया गया है जिससे कि सभी व्यक्ति प्रभावित हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है कि यह नियम के मसौदे को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के बाद ही मान्य एवं स्वीकार किया जायेगा।

यदि कोई भी निरोध या सुझाव प्रशासक के सचिव यादरा, एवं नगर हवेली ने इस नियम के मसौदे के तहत प्राप्त किये हो तो उन्हें 'प्रशासक' द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

1 सक्षिप्त नाम —यह नियम दादरा एवं नगर हवेली के निवारण एवं दुर्घीकरण चकबन्दी अधिनियम, 1983 कहलाया जायेगा।

2 परिभाषा —इस अधिनियम में जब तक कि विषय संदर्भ से कोई बात असंगत न हो।

(अ) अधिनियम में अभिप्रेत है बम्बई निवारण एवं दुर्घीकरण चकबन्दी अधिनियम, 1947।

(ब) फार्म से अभिप्रेत है जो इस नियम के माध्य संलग्न है।

(स) धारा से अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा है।

(ज) इस नियम में शब्द से यह अभिव्यक्त प्रयोग किया जाता है परन्तु इस नियम का तात्पर्य यह नहीं निकाला जाता है कि उसका परिभाषित नियत हो।

3 अखंड क्षेत्र का प्रकाशन —इस अधिसूचना का सरकारी राजपत्र से धारा-4 की उप-धारा -(2) एवं धारा-5 की उप-धारा-3 के अन्तर्गत प्रकाशन के बाद कलेंडर के पृष्ठ में या विषय आया कि उसके साथ क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भी संलग्न किया जाये और जिसे कि तात्पर्य, कश्तरी, तात्पर्य मामलतदार एवं पट्टेनाद या और अन्य निश्चित किये गये प्रत्येक गांवों में क्षेत्रीय भाषा से संबंधित गांव हो वहाँ भेजा जाये।

4. जहाँ पर गांव में कोई निवारक आदि रिकार्ड नहीं मिलता है एव जहाँ पर उन सभी गांवों का सही रिकार्ड नहीं मिलता है जहाँ में प्रविष्ट कर के धारा-6 की उप-धारा (1) द्वारा निम्न फार्म के अनुसार मांगा जाये।

क्र० सं०	सर्वे संख्या	ईनाम	सर्वे सं०	क्षेत्र	साधारण एवं विशेष मूल्यांकन	उप-सं०	
	या क्षेत्र का नाम	क्षेत्री एवं कितने सम्बन्ध समय से शुरू कर रखा है।	भूमि संख्या हस्ता-तरण, रजिस्टर एवं कपत-कारी आदि के ऊपर यदि कोई निर्णय लिया हो।				
1	2	3(अ)	3(ब)	3(क)	4	5	6
क्षेत्र	मूल्यांकन क्षेत्रीय या विशेष या एन. एवं मूल्यांकन अवापसी	क्षेत्रीय भूमिका या मालिक विशेष एवं किस्म एन. एवं मूल्यांकन अवापसी	भूमिका शीर्षक एवं किस्म	उद्भव शीर्षक एवं किस्म	ए. जी. अधिकार या भार या भार में छीक अधिकार का नाम एवं भार	रूपरेखा सं० का परिवर्तन	विवरण
7	8	9	10	11	12	13	14
ए. जी.	रूपरेखा						
IS	कोई भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निश्चित की गई है उसकी बदली के लिये आवेदन पत्र।						

यदि कोई भी व्यक्ति अनुमति ले कर किसी भी भूमि को जो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु धारा-8 ए० की तहत निश्चित की हुई के अन्तर्गत कलेक्टर की सुपुर्ग में बदली के लिये एक आवेदन करें। कलेक्टर यदि उस भूमि पर सहमत है कि वो सही रूप से सार्वजनिक प्रयोग हेतु निश्चित मंजूरी के अंतर्गत बदली के लिये अनुमति हेतु आवेदन करें।

(6) बसव करने का तरीका पत्रिक द्वारा होगा। कोपरेटिव शेयर भूमि के शेयर में आवंटन के भिये या राशि का प्रतिकार के अन्तर्गत धारा-8 ए.ए. की उप-धारा (2) द्वारा जाना। (1) कलेक्टर की कचेरी में सब से पहले किस में को-शेयर की संख्या निश्चित करें जिन्हें भूमि दी जानी है और कितने को-शेयरों की संख्या है जो कि "राश प्रतिकार" को दिया जाना है। सभी का शेयर का निश्चित रूप द्वारा नोटिस दिया जाये कि कलेक्टर की कचेरी में निश्चित की गई नोटिस में तारीख के अनुसार पहले इस किसके तहत हाजिर रहें।

(2) नोटिस में निश्चित की गई तारीख उप-नियम (1) तहत उल्लेखनीय है। या ठीक भविष्य में जिन तारीख को कार्यवाई स्थगित किया गया। कलेक्टर के या न्यायालय में जब के दाखिल किया जाता है तो को-शेयर एवं उन के प्रतिनिधि उप दिन हाजिर रहें।

1. बहुत सी अभिन्न पक्षियां एवं पेपर जो को-शेयर से संबंधित हैं तैयार किये गये हैं।

2. प्रत्येक को-शेयर के अलग सी पर्ची के एक पक्ष तरफ नाम लिखे और सभी नई पक्षियों को अभिन्न पूर्ण तरीके से संलग्न नाम लिखे होने चाहिए।

3. सभी पक्षियों को खामी बाक्स के अन्दर जो कि बराबर साईज का हो वाली जाये और दूर तक बाक्स में शामिल न की जाए।

(4) किसी भी एक को-शेयर को पूछा जाये या किसी और व्यक्ति का जो उस समय हाजिर रहा होगा वहां से (ले जाने के लिए) बाक्स के साथ भूमि तक ले जाने के समय लेकिन बाक्स देखने के बगैर एक एक करके बहुत सी मोटी हुई पक्षियां, उस के नम्बर के को-शेयर को उपनियम (1) के अन्तर्गत भूमि के शेयरों का आवंटन करने के लिए स्थिर करना।

(3) जो को-शेयर जिस का नाम पर्ची पर आया है वो भूमि का शेयर लेने का पहले हकदार है। और जो बाकी को-शेयर है वह प्रतिकार राशि लेने के हकदार है।

(4) यदि नोटिस के अन्दर जो तारीख की गयी थी एवं उप-नियम (1) के अन्तर्गत जारी की गयी थी। सभी एवं ज्यादा संख्या में को-शेयर कलेक्टर न्यायालय में अनुपस्थित थे। उस केम में चिट्ठी डालकर जैसे उप-नियम (2) में दर्शाया गया है उस समय तीन पंच से कम कलेक्टर द्वारा या कोर्ट द्वारा चयन नहीं होना चाहिए।

(7) को-शेयर द्वारा प्रतिकार जमा कराने का तरीका: कलेक्टर एवं कोर्ट भूमि से सम्बन्धित दो भाग है यह निश्चित करने के बाद प्रतिकार की राशि जो प्रत्येक को-शेयर द्वारा (अदा) भूमि की ज्यादा दर द्वारा अदा करनी होती है जो कि को-शेयर द्वारा बालूध में बिना मंजूरी की भूमि दबाई रखी थी। इस सम्बन्ध में को-शेयर का लिखित रूप में नोटिस वे कर बनाया जाये कि राशि जो वो कोर्ट या कोर्ट के साथ कलेक्टर या उन के नजदीक सरकारी खजाने में राशि को प्रतिकार के रूप में 7 दिन के अन्दर राशि जमा करवा/कर, दो जायें।

(8) प्रकाशित अधिसूचना के विभाग 15 के अंतर्गत

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के खण्ड 13 के अंतर्गत प्रकाशित करने के बाद समाहर्ता श्री इस मामले का अंतर्वेत्तु भाषानर का कार्य प्रादेशिक भाषा में प्रत्येक संबंधित गांव में प्रवेश के सामान्यद्वारा की कचहरी और पटेलदा या प्रमुख स्थानों पर विपकाकर और डोल बजा कर प्रकाशित करेंगे।

(9) इस योजना में विवरण (रिकार्ड) अभिलेख और नक्शे में समाविष्ट करना है।

धारा (14) की उप-धारा (1) के अंतर्गत बनाई गई योजना में निम्न विवरण, रिकार्ड एवं नक्शे अनिवार्य होंगे जैसे कि

1. गांव का नक्शा कि जिसमें वर्तमान समय सर्वेक्षण अंक उसके उप-विभाग एवं मान्य रास्ते-गाड़ी मार्ग-पगडंडी और किया गया क्षेत्र जैसे कि दकन और दाह मस्कार भूमि, चगाई क्षेत्र और खलिहान दिखाए गये हों।

2. गांव का दूसरा नक्शा जो उद्देश्य नक्शे (1) की नकल होगी मगर लाल रेखा में या अन्य नियान से प्रदर्शित करना हुआ कि समेकन योजना को लागू करने के बाद वर्तमान सर्वेक्षण अंकों से उनके उप-विभागों मान्य रास्ते गाड़ीमार्ग पगडंडी और सार्वजनिक उद्देश्य हेतु नियत क्षेत्रों की मूल स्थिति में कैसे परिवर्तन होगा।

3 क्षेत्रों के मालिक के नाम-सर्वेक्षण अंक हिस्सा अंक जमीन का वर्ग, अवधि, क्षेत्र मूल्यांकन अन्य हक और मार दिखाता हुआ विवरण (हक का अभिलेखन संपूर्णतः तैयार हो जाने के बाद) ।

4 विवरण कि जिसमें मालिक का नाम कि जिसका नया चकबन्दी क्षेत्र बांटा गया हो ध्यौरे के साथ उस के सर्वेक्षण अंक हिस्सा अंक भूमि पट्टे का वर्ग, क्षेत्र मूल्यांकन एवं दूसरे हक का मार नया क्षेत्र खण्ड है और उसकी संघटन न करने के कारण का स्पष्ट विख्याया गया हो ।

5 सम्बन्धित मालिक को दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति और उस से जुड़न किया गया समेकन का विवरण ।

6 धारा 16 एवं 17 के अनुसरण में अगर कोई कार्यवाई की गई हो तो उसका सक्षिप्त विवरण ।

7 योजना के सम्बन्ध में ग्राम्य समिति द्वारा समेकन अधिकारी को दिये गए सुझाव और उठाई गई आपत्ति कि जिसके लिये अपने द्वारा की गई विरुद्ध व्यवस्था और स्वीकार न करने के कारण का विवरण ।

8 इस सम्बन्ध में समाहर्ता द्वारा अपेक्षित जरूरी वेसे अन्य व्यापार (तकमील) ।

(10) गांव में घटकों में जमीन का समुहिकरण करने की प्रक्रिया :

1. धारा 14 के अंतर्गत चकबन्दी की योजना बनाने के लिए चकबन्दी अधिकारी अपने को उचित लगे उतने घटकों में गांव में जमीन का विभाजन करेंगे, शर्त यह है कि समाहर्ता की पूर्व मजूरी के बिना किसी भी गांव में घटकों की संख्या चार से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए ।

2 चकबन्दी अधिकारी को जमीन का घटकों में विभाजन करने समय निम्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए ।

1. उस गांव में पैदा हुई फसल उसकी जात और संख्या,
2. जमीन का प्रकार,
3. मिचौड़ी व्यवस्था,
4. गांव का स्थल-गांव और पाडा में निवास क्षेत्र का सामीप्य ।

(11) मालिक का नये प्लोट्स नियत करने का ढंग :

चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक मालिक को नये प्लोट्स निम्न रीति में नियत करेंगे ।

अ. अपने क्षेत्र का संघटित करने की दृष्टि से अपनी जमीन का विनिमय का परम्पर स्वीकार करता है उसे ही जमीन नियत की जाये । शर्त यह है कि वैसी स्वीकृति चकबन्दी अधिकारी को लिखित दी जाये और चकबन्दी अधिकारी को ग्राम्य समिति के साथ परामर्श करके समाधान करना चाहिए कि सम्बन्धित मालिक के द्वारा वैसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का सुधार लाया नहीं गया ।

ब. प्रत्येक मालिक का- संभवतः उस घटक में जमीन नियत की जाएगी कि जहां अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और मुख्य मांग धारण करना है या उसका निवास स्थान हो या कायमी सुधार की हुई जमीन धारण करना हो ।

क. किसी भी मालिक को जमीन नियत करने समय ध्यान में रखा जाये कि चकबन्दी अधिकारी उसे उस प्रकार की जमीन नियत करे जैसी कि उसमें ली गई है ।

(12) योजना बनाने में विचाराधीन लेने योग्य अन्य विषय :-

धारा 14 के अंतर्गत चकबन्दी की योजना बनाने में चकबन्दी अधिकारी धारा 14 के उप-धारा (2) में बताये गए विषय के अतिरिक्त एक को खरीदो का हक विमोक्षण है ।

(13) धारा 16 के अंतर्गत घोषणा का प्रकाशन :

धारा 17 के उप-धारा के अंतर्गत घोषणा का प्रकाशन इन दिनों के लिए गांव में घोषणा पत्र की नकल प्रादेशिक भाषा में संबंधित मुख्य रास्ते सड़क एवं पटेल्लाद या गांव के अन्य मुख्य स्थानों पर चिपकाने से किया जायेगा । गांव में डोल बजाकर ऐलान किया जाएगा कि घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया है अगर घोषणा पत्र के लिए कोई विरोध, समाप्ति या क्षति पूर्ति के लिए वाचा मार्शजनात्मक मुख्य मार्ग के अलावा अन्य रास्ते-मार्ग-गली पर हक दावा होंगे । चकबन्दी अधिकारी के समक्ष 30 दिनों में प्रस्तुत करना होगा ।

(14) चकबन्दी अधिकारी द्वारा योजना मसौदों का प्रकाशन :

धारा 11 के अंतर्गत बनाया गया चकबन्दी योजना का मसौदा तबसे के साथ विवरण, सूचि एवं नियम 1 में बताए गए विषयों का प्रकाशन चकबन्दी अधिकारी द्वारा 30 दिनों के लिए उस योजना मसौदे की कापियां प्रादेशिक भाषा में पटेल्लाद या अन्य मुख्य स्थानों पर चिपकाकर किया जाएगा । संबंधित प्रत्येक गांव में डोल बजाकर ऐलान किया जाएगा कि योजना प्रकाशित की गई है अगर कोई आपत्ति हो तो 30 दिनों में चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।

इस प्रदेश के (तहसीलदार) मामलातदार की कचहरी पर प्रादेशिक भाषा में फार्म-1 में सूचना पत्र की कापी 30 दिनों के लिये चिपकाई जाये ।

(15) चकबन्दी अधिकारी द्वारा संशोधित योजना मसौदा का प्रकाशन :

चकबन्दी अधिकारी, धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत संशोधित योजना, सूचना पत्र के साथ फार्म-2 में, नियम 14 की व्यवस्था की रीति से, प्रकाशित करेंगे ।

(16) समाहर्ता द्वारा संशोधित योजना मसौदा का प्रकाशन :

समाहर्ता धारा 19 के उप-धारा (2) की धारा (2) के अंतर्गत संशोधित योजना की कापी 15 दिनों के लिए फार्म 3 में सूचना पत्र के साथ प्रादेशिक भाषा में पटेल्लाद या प्रत्येक गांव के मुख्य स्थानों पर प्रकाशित करेंगे ।

संबन्धित प्रत्येक गांव में डोल बजाकर ऐलान किया जाएगा कि संशोधित योजना प्रकाशित की गई है अगर कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों में समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।

इस प्रदेश के मामलातदार की कचहरी पर सूचना पत्र की कापी फार्म-3 में प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में 15 दिनों के लिये चिपकाई जायेगी ।

(17) पुष्टि की गई योजना का प्रकाशन :

यह घोषित किया जाये कि पुष्टि की गई योजना सरकारी राजपत्र में अनुभाग 20 की उप-अनुभाग की आवश्यकतानुसार प्रकाशित की गई है । चकबन्दी अधिकारी संशोधित योजना की कापी प्रादेशिक भाषा में पटेल्लाद-प्रत्येक गांव के मुख्य स्थानों पर चिपका कर प्रकाशित करेंगे ।

संबन्धित प्रत्येक गांव में डोल बजाकर ऐलान किया जाएगा कि योजना प्रकाशित की गई है ।

इस प्रदेश के मामलातदार की कचहरी पर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में फार्म-4 में सूचना पत्र की कापी चिपकाई जायेगी ।

(18) धारा 20 के उप-धारा (2घ) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बेदखली का ढंग :

धारा 20 के उप-धारा (2घ) के अंतर्गत किसी भी जमीन के लिए किसी भी व्यक्ति की बेदखली की सूचना पत्र चकबन्दी अधिकारी की ओर

से फार्म-5 में उस व्यक्ति को दिया जायेगा कि जिसके पास जमीन का कब्जा होगा और उसे नियत अवधि में जमीन का कब्जा छोड़ना होगा।

(19) धारा 20 के उप-धारा (3) के अंतर्गत अतिपूर्ति जमा करने का ढंग (तरीका)

अतिपूर्ति की रकम किसी भी व्यक्ति से धारा 20 के उप-धारा (3) के अंतर्गत नजदीक के राजकोष में या तो गांव के लेखाकार (पटेलमवादी) को जमा करनी होगी। जमा की हुई रकम के टोकन रूप चालान या गांव के लेखाकार की ओर से दी गई रसीद की कापी चकबंदी अधिकारी का पेश करनी होगी।

(20) धारा 21 के उप-धारा (4) के अंतर्गत क्षेत्र का पुनःनियतन का ढंग :

क्षेत्र में अपने हक का पुनः नियतन चकबंदी अधिकारी की ओर से धारा 20 के उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्न ढंग से किया जायेगा।

चकबंदी अधिकारी ग्राम्य अधिकारी द्वारा या सा इल बजवाकर या प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में पटेलवाद या गांव के मुख्य स्थानों पर सूचना पत्र की कापी बिपकाकर धापित करवाएंगे कि जिस व्यक्ति को जमीन नियत की गई थी और जिसे भूल की थी उस जमीन का पुनः नियतन की प्राप्तिता एवं अरजदार किस क्रम में उसे जमीन नियतन की जाये उस के बारे में अर्जी संयोजित जाये।

इन आवेदन पत्रों का ध्यान में लेकर जो सबसे ऊंची बोली होगी उसे पुनःनियतन की जाएगी।

शर्त यह है कि

1. जहाँ वो और ज्यादा अरजदार के कब्जे में निकटस्थ जमीन है और वे स्वयं खेती करते हैं तो उस बोली के बाव उस क्षेत्र का पुनः नियतन उसे किया जाएगा कि जिसका आवेदन पहले मिला हो।
2. जहाँ वो और ज्यादा अरजदार समान बोली लगाने हैं और उनमें से किसी एक की जमीन निकटस्थ है और वह स्वयं खेती करता है तो जिसकी अर्जी बाव में मिली है उसे क्षेत्र का पुनः नियतन किया जा सकेगा।
3. जहाँ वो और ज्यादा अरजदार बोली लगाने हैं और उनमें से किसी का भी अपना निकटस्थ क्षेत्र नहीं है तो जिसकी पहली अर्जी मिली हो उसे उस क्षेत्र का पुनः नियतन किया जाएगा।

(21) बदली (स्थानांतरण) प्रमाणपत्र का फार्म :

धारा 23 के उप-धारा (1) के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी द्वारा फार्म-6 में या फार्म-7 में आवश्यकतानुसार स्थानान्तर प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(22) धारा 25 के उप-धारा (2) के अंतर्गत अर्जी करने की अवधि.

धारा 25 के उप-धारा (2) धारा (ब) के अंतर्गत कब्जा लेने की अर्जी करने की अवधि उपरोक्त अनुभाग के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी की उद्घोषणा से 21 दिनों की होगी।

(23) नये क्षेत्र को भार और कब्जाधारी बंधकी बनाने का तरीका:

अगर किसी संयाग में जहाँ पट्टाधारी बंधक साही या अन्य भारवाही चकबंदी अधिकारी के पास अनुभाग 28 के उप-धारा (3) के अंतर्गत जमीन के कब्जे के लिए हकदार के रूप उपस्थित हो जाये तो चकबंदी अधिकारी जमीन मालिक का कारण दर्ज नोटिस देकर 15 दिनों में उसका कारण बताने का कहेंगे कि जमीन का कब्जा पट्टाधारी, बंधकसाही या अन्य भारवाही को क्यों नहीं दिया जाय।

अगर मालिक कारण दर्ज नोटिस देते हैं तो चकबंदी अधिकारी को यह संतोष हो जाये कि जमीन मालिक ने जा कारण दिया है वह पर्याप्त नहीं है तो वो जमीन का कब्जा पट्टाधारी, बंधकसाही या अन्य भारवाही को दे सकेंगे और बाब के रिकार्ड में यथायोग्य सुधार करेंगे।

(24) धारा 29 के उप-धारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश को प्रकाशित करने का तरीका

चकबंदी अधिकारी द्वारा धारा 29 के उप-धारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश को नियम 14 के अंतर्गत योजना मसीदे के प्रकाशन के लिये निर्धारित ढंग में प्रकाशित किया जायेगा।

(25) धारा-21 के उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश के खिलाफ अपील.

(1) चकबंदी अधिकारी के प्रकाशित आदेश के 30 दिनों में धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक अपील की जा सकेगी।

(2) वैसी अपील याचिका के रूप में सक्षिप्त और आदेश के विरोध के आधार को स्पष्ट उल्लिखित करके आदेश की प्रति सलग्न करके की जा सकेगी।

(26) गिरवी-शृण-पट्टा या दूसरे बंध को नये जोत में बदलने का तरीका- धारा-28 के उप-धारा (2) के अंतर्गत गिरवी शृण तथा दूसरे बंध का बदलने के समय अनुभाग 29 की उप-धारा 4 के अंतर्गत समाहर्ता के निकाय का ध्यान में रखकर धारा, 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पट्टे का बदलने का आदेश देने समय चकबंदी अधिकारी को निम्न नियमों का पालन करना होगा जैसे कि —

- (1) जहाँ नये जोत की बजाए मूल्य मूलतः भुलागे के सामान हों तो सारे भार जो प्रस्ताव मांगने वाले से लगता है उसे पूर्वीय भाग वाले को बदला जा सकेगा।
- (2) अगर नये जोत का मूल्य वास्तविक रूप में मूलतः मूल्य से ज्यादा है तो गिरवी और बंध का जो पिछले वाले भाग में लगता है उसे अगले भाग वाले को बदला जा सकेगा।

(27) संघटित क्षेत्र की बदलने के लिये आवेदनपत्र और वैसे परिवर्तन के लिए शर्तें:-

- (1) धारा, 31 की दफा (अ) के मुताबिक किसी भी संघटित क्षेत्र में परिवर्तन नहीं लाया जा सकेगा। वैसे परिवर्तन गिरवी के नाते सहकारी भूमि बंधक बैंक प्राथमिक सहकारी समिति की प्राथमिक भूमि बंधक बैंक के पक्ष में संभव नहीं है। अपवाद रूप समाहर्ता की मंजूरी बाब में इस सदर्थ में आवेदन किया जाये।
- (2) समाहर्ता द्वारा संघटित क्षेत्र में परिवर्तन के लिये निम्न शर्तों पर इजाजत दी जा सकेगी है। कृषि भूमि के परिवर्तन संबंधित प्रति बंध संबंध टेनेसी कानून व्यवस्था में अन्तर्निहित हो। क्षेत्र का मालिक पहले के क्षेत्र एवं भूमि अर्जन उत्तराधिकारी को प्राकर करेंगे।

और समाहर्ता द्वारा निश्चित मूल्य पर।

- (1) क्षेत्र का टेनेट उसके उत्तराधिकारी को।
- (2) निकटस्थ क्षेत्र के मुताबिक मालिक को इति यह है कि वह स्वयं खेतीदार हों या तो निकटस्थ क्षेत्र के टेनेट को एव।
- (3) वैसे वास्तविक खेतीदार कि जिसके पास गांव में उनके भरण-पोषण के लिये अपनी अपर्याप्त भूमि हो।

शर्त यह है कि इसके बावजूब भी इस उप-नियम के अंतर्निहित हो क्षेत्र का आपसी विनियम योजना अंतर्गत नियम बिक्री के अलावा और तरीके से समाहर्ता द्वारा मंजूरी दी जा सकेगी। कृषि भूमि के परिवर्तन से संबंधित प्रतिबंध सगत टेनेसी कानून व्यवस्था में अन्तर्निहित हो और जिसके माध्यम विनियम किया है वह पार्टी द्वारा स्वयं उस क्षेत्र में खेती की जाती है।

- (3) जहाँ संघटित क्षेत्र की सहकारी भूमि बंधक बैंक प्राथमिक भूमि बंधक बैंक या प्राथमिक सहकारी समिति के पक्ष में बंधवित बनाई गई है वैसा गिरवी के लिये शर्त यह है कि अंग बैंक और समिति की अदायगी न की होगी तो सारे संघटित क्षेत्र की

गिरवी में रखा जायेगा और गाने संचालित क्षेत्र को फर्ज की वसूली के लिये बेचा जा सकेगा।

(28) धारा 31 (अ) के अन्तर्गत आदेश का प्रकाशन -

धारा-31(अ) के अन्तर्गत आदेश द्वारा आयुक्त के आदेश की प्रति के साथ सूचना पत्र उस गांव की प्रादेशिक भाषा में फार्म सं-8 में पन्द्रह दिनों के लिये पट्टेदार में प्रकाशित की जायेगी या गांव के मुख्य स्थान पर चिपकाई जायेगी। प्रत्येक गांव में ढाल बजाकर घोषित किया जायेगा कि आदेश का प्रकाशन किया गया है और सूचना पत्र की प्रति फार्म सं-8 में पन्द्रह दिनों के लिये प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में मामलातदार की बचहरी पर चिपकाई जायेगी।

(29) धारा-32 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत विभिन्नता समीक्षा का प्रकाशन -

धारा-32 के उप-धारा (1) के अन्तर्गत याचना के विभिन्नता समीक्षा का प्रकाशन सूचना पत्र के साथ फार्म सं-9 में उस गांव की प्रादेशिक भाषा में 30 दिनों के लिये पट्टेदार या गांव के मुख्य स्थान पर चिपका कर किया जायेगा। प्रत्येक गांव में ढाल बजाकर यह भी घोषित किया जायेगा कि विभिन्नता समीक्षा का प्रकाशन किया गया है या सूचना पत्र की प्रति फार्म सं-9 में 30 दिनों के लिये प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में मामलातदार की बचहरी पर चिपकाई जायेगी।

(30) धारा 32 के उप-धारा-(3) एवं 4 अन्तर्गत विभिन्न योजना का प्रकाशन -

विभिन्न योजना का प्रकाशन अधिष्ठान राजपत्र में धारा-32 की उप-धारा (3) एवं 4 के अन्तर्गत किया गया है उस प्रकार की अधिसूचना के बाद भी चकबंदी अधिकारी विभिन्न योजना की प्रति प्रकाशन सूचना पत्र के साथ फार्म सं-10 में गांव की प्रादेशिक भाषा में प्रत्येक गांव के पट्टेदार या गांव के मुख्य स्थान पर चिपकाकर करेंगे। प्रत्येक गांव में ढाल बजाकर यह भी घोषित किया जायेगा कि विभिन्न योजना का प्रकाशन किया गया है इस प्रदेश के प्रादेशिक भाषा में सूचना पत्र की प्रति फार्म सं-10 में ही मामलातदार की बचहरी में चिपकाई जायेगी।

(31) ग्राम्य समिति का संविधान -

(1) चकबंदी अधिकारी आवश्यकतानुसार गांव या गांवों के समूह के लिये ग्राम्य समिति का गठन करेंगे जिसमें दो प्रतिनिधि स्वयं खेती करने वाले जमीन मालिकों के एक प्रतिनिधि कृषि कारगरों का होगा। मगर गांव में जमीन मालिकों की भी स्वयं खेती है उनके पास जमीन का जितना विस्तार है उससे आगे से ज्यादा विस्तार कृषि कारगरों की जमीन का न होना चाहिए। अगर जो विस्तार बैठ जाएगा तो कृषि कारगरों के दो प्रतिनिधि और संचालित प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होंगे। वे पूर्व निर्युक्त दिन को, ग्राम्य अधिकारी द्वारा संचालित गांवों को पत्रों में पर्याप्त रूप में सूचित करेंगे। और जमीन मालिकों और कृषि कारगरों के प्रतिनिधि सामान्य बहुमत में चुनें और ग्राम पंचायत करेंगे। ग्रामपंचायत के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्देशित होंगे।

(2) चकबंदी अधिकारी ग्रामसमिति के कृषि एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में पद करेंगे।

(3) आवश्यकतानुसार चकबंदी अधिकारी द्वारा ग्राम्य समिति की सभा का आयोजन होगा और उस सभा में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सभासदों के बहुमत में लिया जाएगा। सभासदों की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। तीन सभासदों की उपस्थिति में सभा का काम होगा।

(4) जहां ग्राम्यसमिति भूमिमालिक एवं कृषि कारगरों के प्रतिनिधि की पसंदगी करने में निष्फल होंगे या तो ग्राम्य पंचायत अपने प्रतिनिधि नाम निर्देशित करने में असफल रहेगी तो चकबंदी अधिकारी निम्नलिखित रिकार्ड करके ग्राम्य समिति के प्रतिनिधि नाम निर्देशन करेंगे।

(5) गांवों और गांवों के सम्बन्धित चकबंदी योजना प्रवर्धन कर के बाद समिति का विघटन किया जाएगा।

(32) ग्राम्य समिति का अन्य फर्ज एवं कार्य

अनुभाग 34 अ के अन्तर्गत गठित ग्राम्य समिति विनियम द्वारा निर्धारित कार्य एवं फर्ज को अलावा निम्नलिखित कार्य एवं फर्ज का पालन करेगी।

(1) समिति निम्न उल्लिखित विषयों पर चकबंदी अधिकारी को सहायता देगी।

(अ) जिस गांव में भूमिका विभाजन या सामूहिककरण करना है उस की राय एवं वकाफ का विस्तार निश्चित करना।

(ब) भूमि विभाग कि आ सामान्य उद्देश्य के लिए आरक्षित करना है उसका निर्धारण एवं उस उद्देश्य के लिए भूमि का चयन करना।

(क) चकबंदी अधिकारी या समाह्वी द्वारा जैसे दूसरे विषय जिसका निर्देश करना है।

(2) संचालित करने हेतु भेदों का विनिर्णय के लिए मालिकों के बीच आपसी करार करने का प्रयास करना चाहिए।

(3) समिति, योजना की पुष्टि के बाद उसे लागू करने में चकबंदी अधिकारी का सहायता करेगी।

(4) संचालित कार्यवाही के दौरान गांव में भूमि की बदली की गई है तो समिति चकबंदी अधिकारी का उसकी रिपोर्ट करेगी।

(33) पुनर्गठित क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं निर्धारण

(1) जहां पुनर्गठित क्षेत्र के साथ सर्वेक्षण नंबर या सर्वेक्षण नंबर का उपविभाग सम्मिलित है जैसे भाग के क्षेत्रों का निर्णय वास्तविक माप द्वारा लिया जाएगा और उसका मूल्यांकन अधोलिखित आधार से किया जाएगा।

इस प्रदेश में दादरा, नगर हवेली और राजस्थान अधिनियम 1971 अनुभाग 81 के (2) के मुताबिक - सर्वेक्षण नंबर या सर्वेक्षण अक्ष का उल्लेख था।

शर्त यह है कि जहां सर्वेक्षण एवं कार्यकरण रिकार्ड का अस्तित्व नहीं है या उसमें सम्बन्ध अधिनियम की व्यवस्था है, सर्वेक्षण अक्ष या सर्वेक्षण अक्ष के उपखंड मार क्षेत्र के अनुपात में ही मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) जहां पुनर्गठित क्षेत्रों में दादरा, गली, पगडडी मार्ग या तो उस का भाग का जिसका मूल्यांकन सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान के लिए नहीं किया गया है जैसे मार्ग, गली, पगडडी या उसका कोई मार्ग का मूल्यांकन वास्तविक मापन आधार से किया जाएगा।

(अ) सम्बन्धित वर्गीकरण को मूल्यांकन के उचित मानकदर लागू करके दादरा नगर हवेली, राजस्थान अधिनियम 1972 के नियम 56 में जो व्यवस्था है उसी मुताबिक भूमि की कीमत निश्चित की जाएगी छति यह है कि उस नियमों की व्यवस्था के आधार पर।

(ब) सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत कृषि हेतु जिसका विकास किया गया है वैसे भूमि कि जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया उसका मूल्यांकन प्रदेश के अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में नियमों या प्रकीर्ण प्रदेश में असलीकरण में है उस के मुताबिक

किया जाएगा। इति यह है कि जहाँ वैसे नियम या तो प्रक्रिया नहीं है वैसे जमीन का मूल्यांकन धारा (अ) के मुताबिक निश्चित किया जाएगा।

3. क्षेत्र और पुनर्गठित क्षेत्र का मूल्यांकन निम्न दशित क्षेत्र और मूल्यांकन का कुछ होगा।

(अ) सर्वेक्षण अंक या सर्वेक्षण अंक का उपखण्ड का क्षेत्र एवं मूल्यांकन अगर है जिसका संपूर्णतः समावेश पुनर्गठित क्षेत्र में किया गया है।

(ब) सर्वेक्षण अंक या सर्वेक्षण अंक का उपखण्ड का क्षेत्र या मूल्यांकन अगर है जिसका समावेश पुनर्गठित क्षेत्र में किया गया है उपनियम (1) के आधार से निश्चित किया जाएगा।

(क) किसी भी रास्ता, मार्ग, गली या पगडंडी या जो उसका विभाग जिसका समावेश पुनर्गठित क्षेत्र में किया गया है उसका क्षेत्र मूल्यांकन उपनियम (2) के मुताबिक निश्चित किया जाएगा।

(4) जहाँ पुनर्गठित क्षेत्र का भाग पट्टे पर है उसका उसके भाग का क्षेत्र या मूल्यांकन उपनियम (1) में जो तरीके की व्यवस्था है उसी प्रकार अलग निश्चित किया जाएगा।

(5) पुनर्गठित जिनका क्षेत्र और मूल्यांकन उपनियम के अधीन निश्चित किया जाएगा और भूमि रिकार्ड में दशित अंक के अंतर्गत अलग रूप से प्रविष्ट किया जाएगा।

(6) उपनियम (4) के अंतर्गत निश्चित किए गए पुनर्गठित क्षेत्र और मूल्यांकन को भूमि रिकार्ड में उपनियम (5) के अंतर्गत जो अंक दशित किया गया है उसी मुताबिक अलग रूप से भूमि रिकार्ड में प्रविष्ट किया जाएगा कि जो पुनर्गठित क्षेत्र के भाग रूप है।

व्याख्या:—(इस नियम में पानी का दर या हिस्सा समाविष्ट है जिसे मूल्यांकन में समाविष्ट किया गया है) इस नियम के मुताबिक मूल्यांकन के लिए पानी का दर या हिस्सा समाविष्ट है।

34. हक रिकार्ड में सुधार:—

संबंधित योजना के हक रिकार्ड में सुधार, बावरा नगर हबेली के भू-राजस्व नियमन 1971 में रखी गयी व्यवस्था एवं ढंग से चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कार्य—I

(नियम 14 में देखा जाए)

बम्बई की संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982

सूचनापत्र]

सूचित किया जाता है कि चकबन्दी के लिए योजना मसौदा जो गांव मेंतेहसील जिले में स्थित है बम्बई संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1947 के अनुभाग 13 के अधीन बनाया गया है और दिनांक 19..... को उस गांव में पट्टेलादपर प्रकाशित किया गया है।

2. उस योजना से किसी भी व्यक्ति पर असर होने की संभावना है तो वह उस योजना सम्बन्धित अपना विरोध लिखित रूप से दिनांक 19..... के पहले चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा

चकबन्दी अधिकारी

कार्य—II

(नियम 15 में देखा जाए)

बम्बई से विभाजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982

सूचनापत्र

सूचित किया जाता है कि चकबन्दी के लिए योजना मसौदा जो गांव मेंतेहसील में जिले में स्थित है उसे बम्बई संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1947 के अनुभाग 13 के अधीन बनाया गया और उसे बावरा, नगर हबेली संविधान का रोक एवं चकबन्दी नियमन 1983 में किए गए नियम तरीके से दिनांक 19 को अगर उस योजना के लिए विरोध है तो निवेदनार्थ प्रकाशित किया गया।

विरोध प्राप्त हो जाने के बाद विचार करके चकबन्दी अधिकारी द्वारा योजना में सुधारी की गई है और उस अधिनियम के अनुभाग 18 के उपअनुभाग (2) के अधीन उस गांव के पट्टेलाद पर प्रकाशित किया गया।

दिनांक 19.....

चकबन्दी अधिकारी

कार्य—III

(नियम 16 में देखा जाए)

बम्बई संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982

सूचनापत्र

सूचित किया जाता है कि चकबन्दी के लिए योजना मसौदा जो गांव मेंतेहसील में जिले में स्थित है उसे बम्बई संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1947 के अनुभाग 13 के अधीन बनाया गया बावरा, नगर हबेली संविधान का रोक एवं चकबन्दी नियमन 1983 के नियम 14 में किए गए नियम तरीके से दिनांक 19 को अगर उस योजना के लिए विरोध है तो निवेदनार्थ प्रकाशित किया गया।

विरोध प्राप्त हो जाने के बाद विचार करके चकबन्दी अधिकारी द्वारा योजना में सुधारी की गयी है और सुधारी की गयी योजना विरोध के निवेदनार्थ उस अधिनियम के अनुभाग 18 के उप अनुभाग (2) के अधीन पुनः प्रकाशित की गयी। योजना में से अनावश्यक बातों को निकाल कर समाहर्ता द्वारा सुधार कर के उस अधिनियम के अनुभाग 20 के उपअनुभाग 2 के अंतर्गत गांव के पट्टेलाद पर प्रकाशित की गई।

2. उस योजना कि जिसमें अनावश्यक बातों को निकाल कर सुधारी गयी है उससे किसी भी व्यक्ति पर असर होने की संभावना है तो वह उस योजना सम्बन्धित अपना विरोध लिखित रूप से दिनांक 19..... के पहले बावरा, नगर हबेली के समाहर्ता को प्रस्तुत कर सकेगा दिनांक 19.....

समाहर्ता

कार्य—4

(नियम 17 में देखा जाए)

बम्बई संविधान का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982

सूचनापत्र

भूमि मालिक-असायी या अन्य लोग कि जिन्हें भूमि के लिए दिलचस्पी है उन्हें जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि चकबन्दी के लिए योजना जो गांव मेंतेहसील में जिले में स्थित

है उस की बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी आदि नियम 1947 के अनुभाग 19 के अधीन समाहर्ता एवं राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है और उस गांव को पट्टेलाद पर प्रकाशित कर दी गयी है।

दिनांक 19.....

चकबन्दी अधिकारी

फार्म 5

(नियम 18 में देखा जाय)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम, 1947

वेदखली का सूचना पत्र

इन बातों को ध्यान में लेते हुए गांव .. तहसील..... जिले की चकबन्दी योजना की बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी आदि नियम 1947 के अनुभाग 19 के अंतर्गत समाहर्ता/प्रशासन द्वारा पुष्टि कर दी गयी है। संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में दर्शाित जमीन उस व्यक्ति की जिसके सामने स्तंभ 2 में वर्णित गयी है उसे नियत कर दी है। इन बातों को ध्यान में लेते हुए जमीन आपके कब्जे में है। अतः बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1947 अनुभाग 20 के उपअनुभाग (2अ) द्वारा स्वीकृति अधिकार प्रयोग के मुताबिक मैं..... चकबन्दी अधिकारी सूचना पत्र मिलने के बाद..... दिनों में जमीन खाली करने का निर्देश करता हूँ। अगर आप उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी जमीन खाली करने में असफल रहेंगे तो उस जमीन की वेदखली के लिए मैं जैसे कदम उठाऊंगा जो मुझे आवश्यक हों।

अनुसूची

1	2
भूमि का वर्णन	चकबन्दी योजना के अंतर्गत नियतन किया
	क्षेत्र ; गया है उसका नाम।
अनु. नं०	
	ए० जी०

दिनांक..... 19.....

चकबन्दी अधिकारी।

फार्म—6

(नियम 21 में देखा जाये)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982 नियमन के अनुभाग 23 (1) के अंतर्गत दावरा नगर हवेली के चकबन्दी अधिकारी द्वारा मंजूर किया गया बदली प्रमाणपत्र।

इन बातों को ध्यान में लेते हुए चकबन्दी योजना के अंतर्गत गांव में तहसील..... जिले में है कि जिसकी समाहर्ता/प्रशासन द्वारा पुष्टि कर दी गई है और उस संदर्भ में बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1947 के अनुभाग 30 के उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक समाहर्ता/प्रशासन की अधिसूचना नं०..... दिनांक..... के अधिन सरकारी राजपत्र के विभाग..... के पन्ने नं० पर प्रकाशित की गई है।

संलग्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र आपको नियत कर दिया गया है। उस योजना के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि गांव..... तहसील..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी..... के लिए क्षेत्र को बदल दिया जाता है।

अनुसूची

अनु. नं० और क्षेत्र का नाम अगर है	हिस्सा नं०	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	समय अवधि	भार एवं हक्क पर प्रतिबन्ध अगर है
1	2	3	4	5	6
ए० जी०		ह० पैरे			

चकबन्दी अधिकारी ने जमीन की बदली की है और साक्षी के रूप में दिनांक 19..... का पत्रमुद्रा लगाई है।

चकबन्दी अधिकारी

फार्म—7

(नियम 21 में देखा जाय)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982 नियमन के अनुभाग 24(1) के अंतर्गत चकबन्दी अधिकारी द्वारा मंजूर किया गया बदली प्रमाणपत्र, उसके साथ नियमन के अनुभाग 20(4) भी पठा जाय।

इन बातों को ध्यान में लेते हुए चकबन्दी योजना अंतर्गत गांव में..... तहसील..... जिले में कि जिसकी समाहर्ता/प्रशासन द्वारा पुष्टि कर दी गई है और उस संदर्भ में बम्बई संविभजन का रोक एवं चकबन्दी अधिनियम 1982 के अनुभाग 20 के उप-अनुभाग (1) द्वारा आवश्यक समाहर्ता/प्रशासन की अधिसूचना नं०..... दिनांक..... के अधीन सरकारी राजपत्र के विभाग..... के पन्ने पर प्रकाशित की गई है।

संलग्न अनुसूची में निर्धारित क्षेत्र गांव..... तहसील..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी..... को नियत कर दिया गया है।

एवं इन बातों को ध्यान में लेते हुए इस अधिनियम के अनुभाग 20 के उप-अनुभाग (3) द्वारा आवश्यक क्षतिपूर्ति की वसूली जमा करने में श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उस क्षेत्र में जो हक्क नियत किया है, उस क्षेत्र की कीमत की वसूली आपके पास की जाती है।

अतः प्राप्त कीमत को ध्यान में लेकर प्रमाणित किया जाता है कि गांव..... तहसील..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी के लिए उस क्षेत्र को बरत दिया जाता है।

अनुसूची

अनु. नं० और क्षेत्र का नाम अगर है	हिस्सा नं०	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	समय अवधि	भार एवं हक्क पर प्रतिबन्ध अगर है।
1	2	3	4	5	6

चकबन्दी अधिकारी ने जमीन की बदली की है और साक्षी के रूप में दिनांक 19..... को पत्रमुद्रा लगाई गई है।

चकबन्दी अधिकारी

फार्म-8

(नियम 28 में देखा जाय)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चक्रवन्दी अधिनियम 1982

सूचनापत्र

सभी भू-मालिक, काम्पकारों और अन्य लोग जिन्हें जमीन के लिए दिलचस्पी है उन्हें अपनी जानकारी के लिए सूचित किए जाते हैं। चक्रवन्दी योजना जो जिले के तहसील के गांव में स्थित है और उसमें अकस्मिक रूप से गड़बड़ निम्नलिखित/गणितीय त्रुटि/भूल हुई थी उसे सुधारने के लिए दिनांक 19..... के आर्डर सं० सगर्हता द्वारा बम्बई संविभजन का रोक एवं चक्रवन्दी अधिनियम 1947 के अनुभाग 31 के अन्तर्गत पारित कर दिया गया है। और उस गांव के पट्टेलाद पर प्रकाशित किया गया है।

दिनांक 19.....

चक्रवन्दी अधिकारी।

अगर गांव का पट्टेलाद नहीं है तो उस स्थान का नाम प्रविष्ट किया जाय जहां आर्डर विपकाया गया हो।

फार्म 9

(नियम 29 में देखा जाय)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चक्रवन्दी अधिनियम 1982

अधिसूचना

सूचित किया जाता है कि बम्बई के संविभजन रोक एवं चक्रवन्दी आदि नियम 1947 के अनुभाग 32 के उप अनुभाग (1) के अंतर्गत बनाई गई चक्रवन्दी योजना जो जिले के तहसील के गांव में स्थित है उसका विभिन्नता मसौदा उस गांव के पट्टेलाद पर दिनांक 19..... को प्रकाशित किया गया।

2. योजना के विभिन्नता मसौदे का अगर किसी व्यक्ति पर असर होता संभव हो तो वह अपने विरोध लिखित रूप में दिनांक 19..... को या हा के पहले बादरा नगर हवेली संघ प्रदेश के समारहता द्वारा सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को प्रस्तुत कर सकेगे।

दिनांक 19.....

चक्रवन्दी अधिकारी।

अगर गांव का पट्टेलाद नहीं है तो उस गांव का नाम प्रविष्ट किया जाय जहां आर्डर विपकाया गया हो।

फार्म 10

(नियम 30 में देखा जाय)

बम्बई संविभजन का रोक एवं चक्रवन्दी अधिनियम 1982

सूचना पत्र

सभी मालिक, काम्पकारों या अन्य लोग जिन्हें भूमि के लिए दिलचस्पी है उन्हें जानकारी हेतु सूचित किए जाते हैं कि चक्रवन्दी के लिए विभिन्नता योजना जो बम्बई जिले के तहसील के गांव में स्थित है और जो बम्बई संविभजन का रोक एवं चक्रवन्दी अधिनियम 1947 अनुभाग 32 के उप अनुभाग (3) के अंतर्गत बादरा नगर हवेली

प्रशासन द्वारा बनाई गई है उसे उस गांव के पट्टेलाद पर प्रकाशित की गई है।

दिनांक 19.....

चक्रवन्दी अधिकारी

अगर गांव का पट्टेलाद नहीं है तो उस गांव का नाम प्रविष्ट किया जाय जहां आर्डर विपकाया गया हो।

प्रशासक के नाम पर आदेश से
एम०एम० कल्लेकर, प्रशासक के सचिव

ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI (U.T.)

Silvassa, the 3rd April, 1984

NOTIFICATION

No. ADM/RD/924/1984.—The following draft of certain rules which the Administrator, Dadra and Nagar Haveli proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 37 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holding Act, 1947 (Bombay Act No. 62 of 1947) in force in the State of Gujarat and extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli vide Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification G.S.R. 869(E) dated 30th November, 1983, are published as required by sub-section (3) of Section 37 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

Any objections or suggestions, received by the Secretary to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli, at Silvassa with respect to the said draft, will be considered by the Administrator.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Dadra and Nagar Haveli Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Rules, 1983.

2. Definitions.—In these rules, unless the context requires otherwise,—

- (a) "Act" means the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947;
- (b) "Form" means a form appended to these rules;
- (c) "Section" means a section of the Act;
- (d) Words and expressions used in these rules, but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Publication of standard areas.—After a notification under sub-section (2) of Section 4 or sub-section (3) of Section 5 is published in the Official Gazette, the Collector shall cause the contents thereof to be published by affixing translations of the same in the regional language of the taluka kacheri of the taluka Mamlatdar at the Patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village.

4. Entry of Fragments where Record of Rights does not exist.

In a village where there is no Record of Rights, all fragments in such village shall be entered as such as required

by sub-section (1) of Section 6 in the following form :—

Sr. No.	S.No. or name of field	Inam	Area
		Class and how long continu- able	No. in Land Alienation Register and tenure and decision if any
1	2	3(a)	3(b)
			3(c)
			4 He. Are.
Ordinary or Special assessment and Jud.		Sub Division No.	Area
Rs. p.		He Are	Rs. p.
5	6	7	8
			9
			10
Nature and original of title		Other rights or encumbrances with name of right holder or encumbrancer	Reference to mutation day.
11		12	13
			14

5. Application for transfer of any land for specified public purpose.—Any person desiring to obtain permission for transferring any land for any public purpose specified under section 8-A may make an application in that behalf to the Collector. The Collector shall, on being satisfied that the transfer of land is for a public purpose so specified grant the permission applied for.

6. Manner of choosing by lot co-shares for allotment of share of land or money compensation under sub-section (2) of section 8 AA.—(1) The Court, of the Collector, as the case may be, shall first fix the number of co-shares to whom a share of land may be provided and the number of co-shares to whom money compensation may be given and shall call upon all the co-sharers by a written notice to be present before the Court of the Collector, as the case may be, on a date specified in such notice.

(2) On the date specified in the notice referred to in sub-rule (1), or such future date to which the proceedings may be adjourned, the Court or the Collector, as the case may be, shall in the presence of the co-sharers or their representatives, who may be present on that day :—

- prepare as many identical slips of paper as there are co-sharers;
- write the name of each co-sharer on a separate slip on one side and fold all such slips in identical manner so as to completely enclose the name written thereon;
- place all the slips in an empty box of suitable size and thoroughly mix them by shaking the box;
- ask one of the co-sharers or any other person who may be present there to take out from the box with land but without looking at the box, one by one, as many folded slips as the number of co-sharers fixed under sub-rule (1) for allotting share of land.

(3) The co-sharers whose names appear in the slips so taken out shall be entitled to get share of land and the remaining co-sharers shall be entitled to get money compensation.

(4) If on the date specified in the notice issued under sub-rule (1) all or more than half the number of co-sharers

are absent, the Court or the Collector, as the case may be, may draw the lots as provided in sub-rule (2) in the presence of not less than three panchas to be selected by the Collector or the Court.

7. Manner of depositing compensation by a co-sharer.—The Court or Collector making partition of land shall, after determining the amount of compensation payable by each co-sharer in respect of the excess value of land he gets over the share of land legally due to him, call upon the co-sharers concerned by a notice in writing to deposit, in the case of Court, with the Court, and in the case of a Collector, in the nearest Government treasury, the amount of compensation payable by him within one month from the date of receipt of the notice by him. Where the amount is deposited in a Government treasury, the co-sharer shall produce the receipted challan from the treasury before the Collector within seven days from the date of deposit of the amount by him.

8. Publication of notification under section 15.—After a notification under section 13 is published in the official Gazette, the Collector shall cause the contents thereof to be published by beat of drum in each of the villages concerned and by affixing translations of the same in the regional language of the territory or Mamlatdar Kacheri of the territory and at the Patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village.

9. Statement, records and maps to be included in scheme.—A scheme for the consolidation of holdings prepared under sub-section (1) of section 14 shall contain the following statements records and maps, namely :—

- A map of the village showing all the existing survey numbers and their sub-divisions and recognised road, cart-tracks and foot-paths and areas assigned for public purposes such as burial or cremation grounds, grazing areas, or threshing floor;
- another village map which shall be a copy of the one mentioned in (i) but exhibiting in red lines or other marking how the original position of existing survey numbers, their sub-divisions, recognised roads, cart-tracks, foot-paths and areas assigned for

public purposes will be altered after the consolidation scheme becomes operative;

- (iii) a statement showing the names of the owners of holdings with particulars of Survey No., Hissa No., class of land, tenure, area, assessment and other rights or encumbrances, if any (after getting the Record of Rights up-to-date).
- (iv) A statement showing the names of the owners to whom the new consolidated holdings are allotted with particulars of survey No., Hissa No., class of land tenure, area, assessment and other rights or encumbrances, if any, the fact whether the new holding is a fragment and the reasons for not consolidating it.
- (v) a statement showing the compensation to be given or recovered consolidation from the owners concerned;
- (vi) a brief statement as to the action, if any, taken, in pursuance of section 16 and 17;
- (vii) a statement showing the objections and suggestions in respect of the scheme made to the consolidation Officer by the Village Committee, which were not accepted by him, together with the reasons for which they have been overruled by him.
- (viii) Such other particulars as may be required by the Collector in this behalf.

10. Procedure for grouping lands in village into blocks.—(1) In preparing a scheme for the consolidation of holdings under section 14, the Consolidation Officer shall divide the lands in a village into such number of blocks as he may deem appropriate :

Provided that the number of blocks in any village shall not exceed four without the prior approval of the Collector.

(2) In dividing the lands into blocks, the Consolidation Officer shall have regard to the following factors, namely:—

- (i) the kind and number of crops grown in the said village.
- (ii) the quality of the soil;
- (iii) irrigational facilities ;
- (iv) proximity to village site or other residential area in the village or hamlet of it.

11. Manner of allotment of new plots to owners.—The Consolidation Officer shall allot new plots to each owner in the following manner, namely :—

- (a) The owners who mutually agree to exchange their lands with a view to consolidating their holdings may be allotted the lands agreed to be exchanged provided such agreement is given to the Consolidation Officer in writing and the Consolidation Officer, in consultation with the Village Committee is satisfied that no correction of any kind has been brought on the owners concerned to secure such agreement.
- (b) Every owner shall as far as may be feasible be allotted land in the blocks where he—
 - (i) holds the largest and principal part of his holdings; or
 - (ii) has his residential house; or
 - (iii) holds land in which he has made improvement of a permanent nature.
- (c) in allotting new plot of land to any owner in lieu of a plot of land taken away from him, the Consolidation Officer shall, as far as may be feasible allot land of a similar kind as the one which is taken away from him.

12. Other matters to be taken into consideration in preparing a scheme.—In preparing a scheme for the consolidation of holdings under section 14 the Consolidation Officer, shall, in addition to the matters mentioned in sub-section (2) of section 14 have regard to the right of purchase of tenants under the relevant Regulation.

13. Publication of declaration under section 16.—The declaration under sub-section (1) of section 17 shall be published in the village by affixing copies of the same for thirty days at a prominent place on the road, street, lane or path concerned and at the Patelad or other prominent place in the village concerned in the regional language of the village. It shall also be announced in the village by beat of drum that the declaration has been so published and that objections, if any, to the declaration and claims, if any, for compensation on account of the extinction or diminution of any interest or right other than the right of public highway, on or over the said road, street, lane or path should be submitted to the Consolidation Officer within thirty days.

14. Publication of draft scheme by the Consolidation Officer.—The draft scheme of consolidation prepared under section 14 together with the maps, statements, lists and particulars mentioned in rule 2, shall be published by the Consolidation Officer by affixing copies of the same along with a notice in Form I for thirty days at the Patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village. It shall also be announced in each of the villages concerned by beat of drum that the scheme has been so published and that objections, if any, should be submitted to the Consolidation Officer, within thirty days. A copy of the notice in Form I shall also be affixed for thirty days at the Mamlatdar office of this territory of regional language of the territory.

15. Publication of amended draft scheme by Consolidation Officer.—Consolidation Officer shall publish the amended scheme together with a notice in Form II under sub-section (2) of section 18 in same manner as is provided in rule 14.

16. Publication of amended draft scheme by Collector.—The Collector shall publish the further amended scheme under clause (d) of sub-section (2) of section 19 by affixing a copy thereof along with a notice in Form III for fifteen days at the Patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village. It shall also be announced in each of the villages concerned by beat of drum that the amended scheme has been so published and that objections, if any, should be submitted to the Collector within fifteen days. A copy of the notice in Form III shall also be affixed for fifteen days at the Mamlatdar office of this territory in the regional language of the territory.

17. Publication of confirmed scheme.—After the notification stating that the scheme as confirmed is published in the Official Gazette as required by sub-section (1) of section 20, the consolidation Officer shall cause the scheme as confirmed to be published by affixing copies of the same at the Patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village. It shall also be announced in each such village by beat of drum that the scheme has been so published. A notice in Form IV shall also be affixed at the Mamlatdar office in the regional language of the territory.

18. Manner of eviction of any person from land under sub-section (2-A) of section 20.—Eviction of any person from any land under sub-section (2-A) of the section 20 shall be made by the Consolidation Officer by serving notice in Form V on the person or persons in possession requiring them within such time as may appear reasonable after receipt of the said notice to vacate the land and if such notice is not obeyed by removing physically or deputing a subordinate to remove physically any person who may refuse to vacate the same.

19. Manner of depositing compensation under sub-section (3) of section 20.—The amount of compensation to be deposited by any owner under sub-section (3) of section 20 shall be deposited by him in the nearest Treasury or paid

to the village Accountant Palet Telat of the village concerned and a copy of the challan in token of credit in the Treasury or as the case may be the receipt granted by the village Accountant, shall be produced by him before the Consolidation Officer.

20. Manner of reallocation of a holding under sub-section (4) of section 21.—The right in a holding shall be reallocated by the Consolidation Officer under sub-section (4) of section 20 in the following manner:—

The Consolidation Officer shall announce in the village concerned through the village officer and by beat of drum and also by affixing a notice in the regional language of the territory at the Patelad or other prominent place in the village, the fact of the default committed by the person to whom the holding was allotted and of its availability for reallocation and invite applications stating the value at which the applicant may wish it to be allotted to them. After considering these applications, the Consolidation Officer shall reallocate the holding to the highest bidder.

Provided that—

- (i) where two or more applicants who own the adjoining holding or holdings and cultivate them personally, offer the same bid, the holding may be reallocated to him whose application was received first;
- (ii) where two or more applicants offer the same bid and one of them owns the adjoining holding or holdings and cultivates them personally, the holding may be reallocated to the latter applicant; and
- (iii) where two or more applicants offer the bid and none of them owns the adjoining holding or holdings, the holding may be reallocated to him whose application was received first.

21. Form of certificate of transfer.—The certificate of transfer under sub-section (1) of section 23 shall be given by the Consolidation Officer in Form VI or Form VII, as the case may require.

22. Period for making application under sub-section (2) of section 25.—The period for making an application for possession under clause (b) of the sub-section (2) of section 25 shall be twenty-one days, from the date of the proclamation in the village by the Consolidation Officer under the said section.

23. Procedure for putting mortgage or other encumbrancer into possession of new holding.—In case where a lessee, mortgagee or other encumbrancer appears to the Consolidation Officer to be entitled to possession of a holding under sub-section (3) of the section 24, the Consolidation Officer shall issue a notice to the owner to show cause within fifteen days why the lessee, mortgagee or other encumbrancer, as the case may be, should not be put into possession of his holding. If the owner fails to show cause or if the Consolidation Officer is satisfied that the cause shown by the Owner is not adequate, he shall put the lessee, mortgagee or other encumbrancer, as the case may be, into possession of the holding and get the Record of Rights in respect of the holding corrected accordingly.

24. Manner of publication of order passed under sub-section (1) of section 29.—The copy of the order passed by the Consolidation Officer under sub-section (1) of section 29 shall be published in the manner prescribed for the publication of a draft scheme of Consolidation under rule 14.

25. Appeal against order under sub-section (1) of section 29.—(1) Every appeal under section 29 shall be made within thirty days from the date of publication of the order of the Consolidation Officer.

(2) Such appeal shall be made in the form of petition, briefly and clearly specifying the grounds of objection to the order appealed against and shall be accompanied by a copy of such order.

26. Manner of transferring or mortgage, debt, lease or other encumbrance to new holdings.—In transferring a mortgage, debt or other encumbrance under sub-section (11) of section 28 and subject to the decision of the Collector under sub-section (4) of section 29 in ordering a transfer of a lease under sub-section (1) of section 29, the Consolidation Officer shall observe the following rules, namely:—

- (i) Where a new holding is of the same market value as the original one, the whole of the encumbrances attaching to the latter shall be transferred to the former;
- (ii) If the new holding is of a substantially greater market value than the original one, the mortgage and other encumbrances attaching to the latter shall be transferred to the former subject to the condition that the mortgagee and other creditors will agree to such reasonable reduction in the rate of interests as may be fixed by the Consolidation Officer having regard to the substantially better security provided by the new holding and that the lessee shall pay to the owner, subject to the provisions of the relevant tenancy law, such reasonable rent in respect of the new holding as might be fixed by the Consolidation Officer.

27. Application for permission for transfer of consolidated holding and the conditions for such transfer.—(1) No consolidated holding shall be transferred as provided by clause (a) of section 31 (such transfer not being a mortgage in favour of a co-operative land mortgage bank a primary land mortgage bank of a primary co-operative society) except with the permission of the Collector after making an application to him in that behalf;

(2) The transfer of a consolidated holding may be permitted by the Collector subject to the condition that the owner shall, subject to the provisions contained in the relevant tenancy law relating to restrictions on transfers of agricultural lands, and acquisition of holding and lands, first offer it in succession and at the price fixed by the Collector to (i) the tenant of the holding of his heirs, (ii) the owner of the adjoining holding provided he cultivates it personally or to the tenant of the adjoining holding, and (iii) such bona fide cultivators in the village as have insufficient land of their own for their maintenance;

Provided that notwithstanding anything contained in this sub-rule, mutual exchange of holdings, allotted under the scheme, other than by sale, may, subject to the provisions contained in the relevant tenancy law relating to restrictions on transfers of agricultural lands and acquisition of holdings and lands, be permitted by the Collector, if the holdings are cultivated personally by the parties to the exchange.

(3) Where a consolidated holding has been mortgaged in favour of a co-operative land mortgage bank, a primary land mortgage bank or a primary co-operative society, such mortgage shall be subject to the condition that the whole of the consolidated holding shall be deemed to have been mortgaged and in case of default in payment of the loan to the bank or as the case may be, the society the whole consolidated holding shall be liable to be sold for recovery of the arrears of loan.

28. Publication of order under section 31-A.—The order made by the Settlement Commissioner under section 31-A, shall be published by affixing a copy of the same together with a notice in Form VIII for fifteen days at the patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such village. It shall also be announced in each of the villages concerned by beat of drum that the order has been so published. A copy of the notice in Form VIII shall also be affixed for fifteen days at the Mamlatdar office in the regional language of the territory.

29. Publication of draft variation under sub-section (1) of section 32.—The draft variation of a scheme under sub-section (1) of section 32 shall be published by affixing a copy of the same together with a notice in Form IX, for thirty days at the patelad or other prominent place in each of the villages concerned in the regional language of such

village. It shall also be announced in each village by beat of drum, that the draft variation has been so published. A copy of the notice in Form IX shall also be affixed for thirty days at the Kacheri of the Mamlatdar in the regional language of the territory.

30. Publication of varied scheme under sub-section (3A) of section 32.—After the notification stating that the scheme has been varied is published in the official Gazette under sub-section (3-A) of section 32, the Consolidation Officer shall cause the scheme so varied to be published by affixing copies of the same together with a notice in Form X at the patelad or other prominent place in each of the village concerned in the regional language of such village. It shall also be announced in each such village by beat of drum that the scheme so varied has been so published. A copy of the notice in Form X shall also be fixed at the Kacheri of the Mamlatdar in the regional of the territory.

31. Constitution of Village Committee.—(1) The Consolidation Officer shall constitute a Village Committee for village or group of villages, as may be deemed necessary by him, consisting of two representatives of land-owners cultivating land personally, one representative of tenants, if the extent of lands held by the tenants in the village does not exceed half the extent of the land held and cultivated personally by the land-owners in the village and two representatives of tenants if it so exceeds and a representative of each of the Village Panchayats concerned. He shall on a previously appointed day, notice of which shall be given by him to the villages concerned sufficiently in advance through the village officers, hold a meeting of the adult villagers of the village or villages as the case may be for the purpose of electing by a simple majority the representatives of land-owners and tenants. The representative of the Village Panchayat shall be nominated by the Village Panchayat.

(2) The Consolidation Officer shall select one of the members of the Village Committee to be the Chairman of the Committee.

(3) The Village Committee shall meet as and when required by the Consolidation Officer and shall decide all questions by a majority of votes of the members present and voting. The Chairman shall have a casting vote in case of equality of votes. The quorum for meeting shall be three.

(4) Where the adult villagers fail to select the representative of land owners and tenants or where the Village Panchayats fails to nominate its representative, the Consolidation Officer shall after recording reasons in writing, nominate the representatives of the Village Committee.

(5) The Committee shall stand dissolved after the consolidation scheme in respect of the villages or village, as the cases may be, is enforced.

32. Other duties and functions of Village Committee.—The Village Committee constituted under section 34A shall discharge and perform the following duties and functions, in addition to these imposed or assigned by the Regulation, namely :—

- (1) It shall advise the Consolidation Officer in the matters specified below :—
 - (a) Fixing the number and extent of blocks in which the lands in the village may be divided and grouped.
 - (b) Determining the extent of land which may be reserved for any common purpose and selecting land for the said purpose.
 - (c) Such other matters as may be referred to it by the Consolidation Officer of the Collector.
- (2) It shall endeavour to bring about mutual agreements between owner for exchange of holdings with a view to consolidating them.
- (3) It shall assist the Consolidation Officer in enforcing the scheme after it is confirmed.

- (4) It shall report to the Consolidation Officer any transfers of land which may have taken place in the village during the continuance of the consolidation proceedings.

33. Determination of area and assessment of reconstituted holdings.—(1) Where the reconstituted holding includes a portion of a survey number or a sub-division of a survey number, the areas of such portion shall be determined by actual measurement and the assessment shall be determined as mentioned below :—

In the territory, according to sub-section (2) of section 81 of Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Regulation, 1971, as if the portion of the survey number or of the sub-division of a survey number, as the case may be, was a sub-division of a survey number.

Provided that where the survey and the classification records do not exist, or where the rules, under the provisions of the relevant Regulation, the assessment shall be fixed in the same proportion as the areas of the portion bears to the whole area of the survey number or the sub-division of a survey number, as case may be.

(2) Where the reconstituted holding includes any road, street, lane or path or a portion thereof which has not been assessed for land revenue under the relevant Regulation, the area of such road, street, lane, or path or a portion thereof shall be determined by actual measurement and the assessment shall be determined :—

- (a) By applying the appropriate standard rate of assessment to the relative classification value of the land determined in accordance with the provisions of rule 56 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Rule, 1972, subject to the provisions of rule of the said rules; and
- (b) in the case of the other areas of the territory according to the rules or procedure in force in the area for the determination of assessment of un-assessed lands, disposed of for the purpose of agriculture under the relevant Regulation.

Provided that where no such rule or procedure has so far been framed, the assessment of such land shall be determined in accordance with clause (a).

(3) The area and assessment of a reconstituted holding shall be the aggregate of the following areas and assessments :—

- (a) the area and assessment of the survey number or the sub-division of a survey number, if any, wholly included in the reconstituted holding;
- (b) the area and assessment of a portion of a survey number or of a sub-division of a survey number, if any included in the reconstituted holding, determined according to sub-rule (1); and
- (c) the area and assessment of any road, street, lane or path or a portion thereof included in the reconstituted holding, determined according to sub-rule (2).

(4) Where a portion of the reconstituted holding is burdened with a lease, the area and assessment of such portion and the area and assessment of the remaining portion of the reconstituted holding shall be determined separately in the manner provided in sub-rule (1).

(5) The area and assessment of the reconstituted holding determined under sub-rule (3) shall be separately entered under an indicative number in the land records.

(6) The area and assessment of the portions of the reconstituted holding determined under sub-rule (4) shall be separately entered in the land records under indicative subordinate to that of the indicative number given under sub-rule (5) to the reconstituted holding of which they are portions.

EXPLANATION.—The terms 'assessment' in this rule includes the water rate or share, if any, included in the assessment.

34. Correction of Record of Rights.—In accordance with a scheme of consolidation of Record of Rights shall be corrected by the Consolidation Officer in the manner laid down in the territory under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971

FORM I

(see rule 14)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given that the draft scheme for the consolidation of holdings situate in thevillage tehsil/taluka.....district, has been prepared under scheme, may submit in writing his objection relating to the Consolidation of Holdings Act, 1947, and published on theday of.....19.....at the Patelad in the said village.

2. Any person who is likely to be affected by the said scheme, may submit the writing his objection relating to the scheme to the Consolidation Officer after on or before theday of.....19.....

Dated the.....day of.....19.....

Consolidation Officer.

FORM II

(see rule 15)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given that the draft scheme for the consolidation of holdings situate in.....village.....taluka/tehsil.....district was prepared under section 13 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947, and published in the manner prescribed in rule 14 of the Dadra and Nagar Haveli Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holding, Rules, 1983, on the.....day of.....19..... for inviting objections, if any, to the said scheme. On consideration of the objections received the scheme is amended by the Consolidation Officer and is published under sub section (2) of section 18 of the said Act at the patelad in the said village.

Any person who is likely to be affected by the said amended scheme may submit in writing his objection relating to the amended scheme to the Consolidation Officer on or before theday of.....19.....

Dated the.....day of.....19.....

Consolidation Officer.

FORM III

(See rule 16)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given that the draft scheme for the consolidation of holdings situate in.....village.....taluka/tehsil.....district, was prepared under section 13 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947, it was published in the manner prescribed in rule 14 of the Dadra and Nagar Haveli Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holding Rule, 1983, on the.....day of.....19..... for inviting objections, if any, to the said scheme. On consideration of the objections received, the scheme was amended by the Consolidation Officer and the amended scheme was re-published

under sub-section (2) of section 18 of the said Act for inviting objection, if any, to the said amended scheme. On consideration of the objections received the (amended) scheme is (further) amended by the Collector and is published under sub-section (2) of section 20 of the said Act at the patelad, the said village.

2. Any person who is likely to be affected by this (further) amended scheme, may submit in writing his objection relating to the scheme to the Collector, Dadra and Nagar Haveli on or before the.....day of.....19.....

Dated the.....day of.....19.....

Collector.

*To be deleted where not necessary.

FORM IV

(see rule 17)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given for the information of all owners, tenants and other persons having interest in land that the scheme for the consolidation of holdings situatevillage.....taluka/tehsil.....district, as confirmed by the Collector, State Government under section 19 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holding Act, 1947, has been published at the patelad in the said village.

Dated the.....day of.....19.....

Consolidation Officer.

FORM V

(see rule 18)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE OF EVICTION

Whereas in the scheme for the consolidation of holdings of village.....taluka/tehsil.....district..... confirmed by the Collector/Administrator under section 19 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947, land(s) specified in column 1 of the appended schedule has/have been allotted to the person(s) specified against it/them in column 2 thereof.

And whereas you are in possession of the said land(s).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 20, of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act 1947, I.....Consolidation Officer, hereby direct you to vacate the said land(s) within.....day after receipt of this notice. In case you fail to vacate the land(s) referred to above, I shall take such steps as I may deem necessary for evicting you from the said land(s).

SCHEDULE

Description of land(s)	Name of allottee under the Consolidation scheme.
Serial No.	Area
1	2

A.G.

Dated the day of.....19.....

Consolidation Officer.

FORM VI

(see rule 21)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947Certificate of Transfer granted by the Consolidation Officer
under section 23(1) of the Regulation

Whereas under the scheme for the consolidation of Holdings in village.....taluka/tehsil.....district..... which has been confirmed by the Collector/Administrator and in respect of which a notification stating that the scheme

has been confirmed has been published at pages.....of part.....of the Govt. of India Gazette dated the..... day of.....19..... under Collector/Administrator, Notification No.dated the.....day of.....19.....as required by sub-section (1) of section 0 of Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947, the holding described in the schedule hereto annexed has been allotted to you.

Now, this is to certify that the said holding has been transferred to you, Shri/Shrimati/Kumari.....resident of villagetaluka/tehsil.....district..... in pursuance of the said scheme.

SCHEDULE

Sr. No. and name of field, if any	Hissa No.	Area	Assessment	Tenure	Encumbrances and restrictions on right if any
1	2	3	4	5	6
A.g.		Rs. Np.			

In witness where of the Consolidation Officer has hereto set his hand and the seal of his office This,day of.....19.....

Consolidation Officer.

SEAL.

FORM VII

(see rule 21)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947Certificate of transfer granted by the Consolidation Officer
under section 24(1) read with section 20(4) of the Regulation.

Whereas under the scheme for the consolidation of holding in village.....taluka/tehsil.....district.....which has been confirmed by the Collector/Administrator and in respect of which a notification stating that the scheme has been confirmed has been published at page.....of part.....of the Govt. of India Gazette dated the.....day of.....19... under Collector/Administrator's Notification No.dated the.....day of.....19.....as required by sub-section (1) of section 20 of the Bombay Prevention of Fragmenta-

tion and Consolidation of Holdings Act, 1947, the holding prescribed in the schedule hereto annexed was allotted to Shri/Shrimati/Kumari.....resident of villagetaluka/tehsil.....district.....

And whereas the said Shri/Shrimati/Kumari..... has failed to deposit the compensation recoverable from him/her as required by sub-section (3) of section 20 of the said Act.

And whereas the right in the said holding of the said Shri/Shrimati/Kumari..... has been allotted to you under sub-section (4) of section 20 of the said Regulation recovering the value of the said holding from you.

Now, therefore, this is to certify that the said holding has been transferred to you, Shri/Shrimati/Kumari..... resident of village.....taluka/tehsil.....district..... in consideration of the value received.

SCHEDULE

Sr.No. and name of field,if any.	Hissa No.	Area	Assessment	Tenure	Encumbrances and restrictions on right if any
1	2	3	4	5	6
A.g.		Rs. Np.			

In witness where of the Consolidation Officer has hereto set his hand and the seal of his office this,day of..... 19.....

Consolidation Officer.

SEAL

FORM VIII

(see rule 28)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given for the information of all owners, tenants and other persons having interest in land, that Order No. dated the.....day of.....19.....to correct clerical/arithmetic mistakes/error(s) which have arisen from

accidental slips error in the scheme for the consolidation of holding situated in the village of.taluka/tehsil..... district.....has been passed by the Collector under section 31A of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 and has been published at the patlad^a in the said village.

Dated the.....day of.....19.....

Consolidation Officer.

^aIf the village has no patlad, here enter the name of the place where the order is affixed.

FORM IX

(see rule 29)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given that the draft of the variation of the scheme for the consolidation of holdings situate in the village of in the taluka/tehsil district has been prepared under sub-section (1) of section 32 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 and published on the day of 19. at the patelad in the said village.

2. Any person who is likely to be affected by the said draft variation of the scheme may submit in writing his objection to the Secretary to the Administrator of Union Territory on or before the day of 19.

Dated the day of 19.

Consolidation Officer.

*If the village has no patelad, here enter the name of the place where the draft variation is affixed.

FORM X

(see rule 30)

BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947

NOTICE

Notice is hereby given for the information of all owners, tenants and other persons having interest in land that the variation of the scheme for the consolidation of holdings situate in the village of taluka/tehsil district made by the Administrator under sub-section (3) of section 32 of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947, has been published at the patelad* of the said village.

Dated the day of 19.

Consolidation Officer.

*If the village has no patelad, here enter the name of the place where the draft variation is affixed.

By Order and in the Name of Administrator,
S. S. KOLVEKAR, Secy. to the Administrator

